



राजनीतिक अपराधीकरण का आर्थिक विकास पर प्रभाव

डॉ० अंजीत कुमार चौधरी
बी०ए०, एम० ए० (राजनीति विज्ञान), पी-एच० डी०
ल० ना० मि० विश्वविद्यालय, दरभंगा.

भूमिका

एक समय था जब साध्य की तुलना में साधन को सर्वोपरि स्थान दिया जाता था। उस समाज में सच्चे, कर्तव्यपरायण, सद्चरित्र व्यक्तियों को धनी, बलवान और अधिकारपूर्ण की तुलना में अधिक वरीयता दी जाती थी, लेकिन आज लगता है कि वर्तमान भौतिकवादी युग में सब कुछ बदल गया है। आज किसी शीर्ष स्थान पर पहुँचना महत्वपूर्ण है, वहाँ किस तरह पहुँचा गया है, इसका कोई महत्व नहीं है। सब कुछ भौतिक सुख-सुविधाओं के संग्रहण पर केन्द्रित हो गया है। एक देश के विकास को आज केवल भौतिक विकास के आधार पर ही मापा जाता है। इसी कारण से धन इकट्ठा करने के लिए किसी भी अपराधिक कार्यों का सहारा लेना आज आम बातें हो गई है।

वर्तमान में हम संसार की छठी परमाणु अंतरिक्ष व हथियार निर्माता, तीसरी सैनिकों की संख्या, प्रोफेशनल व दूरसंचार, पांचवीं उपग्रह निर्माण, प्रथम हथियार आयातक व द्वितीय मानव शक्ति की श्रेणी में आ गये हैं। सूर्य से लेकर उपग्रह तक का निर्माण हमारे यहाँ होने लगा है। टेलीविजन, फ्रीज, रेडियो, कूलर, सोफा, स्कूटर जैसी वस्तुएं जरूरी आवश्यकताओं व टेलीफोन, रंगीन टी० वी०, सूट, शराब, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, सिनोमा विलासिता की श्रेणी में नहीं रहीं हैं। उपभोक्ता संस्कृति की पहुँच गांवों तक हो गई है। सड़कों, रेलों दूरसंचार के साधनों, फैशन आदि के कारण गांव कस्बे शहरों में तेजी से परिवर्तित होते जा रहे हैं।

आधुनिकतम उत्पाद, तकनीक प्रबंध व्यवस्था, पूंजी निर्माण की दर, बैंकिंग, बीमा व विदेशी व्यापार की स्थिति, कंप्यूटर विकास, विदेशी पूंजी विनियोग आदि क्षेत्रों में हमारी गिनती विकसित राष्ट्रों में होने लगी है। संसार के प्रायः हर देश में हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रबंधक, वित्त विशेषज्ञ व प्राध्यापक कार्यरत हैं, तथा बीसों अविकसित राष्ट्र हमारे ही सहयोग से विकास की ओर बढ़ रहे हैं।

नयी आर्थिक नीति ने विश्व अर्थव्यवस्था में हमें केन्द्र बिन्दु बना दिया है। अब तो बड़ी संख्या में शराबघर, जुआघर, रेस्टारेंट, होटल, नाईट क्लब आदि सब कुछ बढ़ रहे हैं। इस संबंध में कुछ निष्कर्ष निकालने से पूर्व यह जान लेना भी अति आवश्यक है कि 10 पंचवर्षीय व तीन वार्षिक योजनाओं के बावजूद भी संसार में सर्वाधिक गरीब, निरक्षर, बेरोजगार, बाल श्रमिक, विवाहित, अवयस्क, भिखारी, वेश्याएं, बीमार, असहाय, मानसिक रोगी, तथा कोही भारत में हैं इतना ही नहीं, दुर्भाग्य से इन सबकी संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है। ऐसी ही स्थिति बेसहारा वृद्धों, निराश नारियों की है। सुखा व बाढ़ पीड़ितों, दुर्घटनाओं में मरने वालों, असहाय रोगों से पीड़ितों, आत्महत्याओं, हत्याओं, चोरी, डकैतियों, अपहरणों, फिरौती की घटनाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से भी बढ़ रही है। देश के लाखों गांवों के निवासी बिजली, पानी, चिकित्सा, आवास, यातायात के साधन जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित है। अधिकांश

स्कूल आज भी आसामान के नीचे व एक अध्यापक के सहारे चलते हैं। करोड़ों लोग चिकित्सा के नाम पर झाड़-फूंक, जन्तर-मंतर, ओझा, फकीर, डोरा, ताबीज, व नीम-हकीमों पर ही निर्भर करते हैं। भीतरी क्षेत्र के करोड़ों निवासियों के लिए आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था, रेल, सड़क जैसे यातायात के साधन, रेडियों व टीवी की आवाज, विद्यालय की पढ़ाई, सलीके के वस्त्र स्वप्नलोक की बातें बनी हुई हैं।

भ्रष्टाचार के कारण अर्थव्यवस्था को क्षति

यह यथार्थ है कि राजनीतिक अपराधीकरण या भ्रष्टाचार के कारण धन तो देश में ही रहता है पर भ्रष्टाचार के कारण अर्थव्यवस्था को निम्न क्षति होती है।

- गैर उत्पादित कर्मों में लोग प्रवृत्त होते हैं जिस कारण आर्थिक प्रगति की गति धीमी हो जाती है। वर्तमान आर्थिक जगत् का मूलमंत्र है— उत्पन्न करो अथवा नष्ट हो जाओ।
- भ्रष्ट साधनों से अर्जित धन दिखावे, प्रदर्शन एवं उपभोक्ता कार्यों में खर्च होता है जिसकी उपयोगिता कुछ नहीं होती। इससे व्यक्ति का चरित्र नष्ट होता है। उसके परिवार में अनुशासनहीनता बढ़ती है, स्वेच्छाचारिता बढ़ती है तथा वह मानसिक दुश्चिंता के कारण विभिन्न बीमारियों का शिकार होकर अक्षम हो जाता है।
- भ्रष्ट साधनों द्वारा लाभ देखकर मेहनतकश एवं ईमानदार व्यक्ति हताश होते हैं एवं समाज या देश में सामान्य हताशा का परिवेश उत्पन्न होता है। दूसरी ओर भ्रष्ट व्यक्ति अपने चरित्र के साथ दूसरों के चरित्र का भी हनन करते हैं।
- भ्रष्टाचार की चर्चाएँ सुनकर तथा देखकर किशोर एवं युवा पीढ़ी में बिना परिश्रम किये बड़ी-बड़ी महात्वाकांक्षाएँ उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि उन्हें समाज में सभी वस्तुएँ मुफ्त में उपलब्ध संभव प्रतीत होती हैं। फलतः समाज या देश की भावी पीढ़ी पतित हो जाती है।

भ्रष्टाचार की प्रक्रिया में विलंब अन्तर्निहित है। कुछ व्यक्तियों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकारी योजनाओं एवं कार्यों में अनावश्यक मूल्य वृद्धि हो जाती है जिसका बोझ साधारण जनता पर पड़ता है।

- अनिर्णय, निर्णय में विलंब, कार्यालय में विलंब या कम काम करना भी भ्रष्ट आचरण है। “एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में $6\frac{1}{2}$ घंटे में एक लिपिक लगभग $2-2\frac{1}{2}$ घंटे काम करता है।” यह देश के प्रति भ्रष्टाचार होता है भ्रष्टाचार एक ऐसा जीव है जिसके गर्भ से केवल अवैध संतानें उत्पन्न होती हैं एवं यह अंतहीन कुचक्र चलता ही रहता है।

आज भी करोड़ों महिलाओं को खुले में शौच व पेयजल के लिए मीलों पैदल जाना होता है, प्रसव के लिए निखट्ट, अनपढ़ व अप्रशिक्षित दाई की शरण में जाना होता है, धुआं वाले वातावरण में खाना पकाने की मजबूरी के कारण कम दृष्टि व दमा का शिकार होना पड़ता है। अधिकांश प्रतिशत महिलाएं अपने विकास के लिए बनायी योजनाओं से अनभिज्ञ हैं। विधवा, परित्याक्ता व अविवाहित महिलाओं की दयनीय स्थिति में आधारभूत परिवर्तन नहीं आ सका है। विकास के लिए सकारात्मक मानसिकता में परिवर्तन का जो आधारभूत तत्व है, उस दृष्टि से तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं। विचारों की संकीर्णता, सेच की सार्थकता व क्रिया की कूपमंडपता उसी प्रकार बनी हुई है। नारी विकास की उतनी योजनाएं बन जाने के बाद भी द्वितीय श्रेणी की नागरिकता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पुरुष की गुलामी के प्रतीक मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायजेब, गले में मंगलसूत्र, करवा चौथ का व्रत जैसे प्रतीकों को अभी भी उसी प्रकार ढोना पड़ रहा है। समृद्ध व पढ़े-लिखे परिवारों में भी विधवा को मंगल कार्यों से दूर रखने, पुत्री प्राप्ति पर मायूस होने व उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने, उसकी पढ़ाई को अनावश्यक मानने, कानून होने पर भी उसे सम्पत्ति में हिस्सा नहीं देने, शादी के संबंध में उससे विचार-विमर्श नहीं

करने, संतान नहीं होने पर उसे जली-कटी, सुनाने, पुत्र के अभाव में सामाजिक रूप से उसे उत्पीड़ित करने के संबंध में विकासवादी दृष्टि जैसा कुछ भी नजर नहीं आता है।

हमारे यहां शराब, सिगरेट, हेरोईन से लेकर चाय, चुटकी, जर्दा आदि की खपत बढ़ती जा रही है, तथा महिलाएं भी इन सबमें तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। सेक्स संबंधी वर्जनाएँ समाप्त हो रही हैं। अश्लील फिल्मों को परिवार के साथ बैठकर देखने, वी. टी. की गंदगी को सहन करने और सूचनापूर्ण कार्यक्रमों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस विकास ने ता जल्दी सोने व उठने, बड़ों के पांव छूने, हल्का-फुल्का व्यायाम करने, प्रातःकाल समाचार-पत्र पढ़ने, शाश्वत शक्ति याद करने, रिश्तेदारों को मिलने, भेंटने, परिवार में मिलजुल कर चर्चा करने, तथा समाज व राष्ट्र के बारे में सोच सकने की संभावनाएं ही समाप्त कर दी हैं। बड़े शहरों में तो प्रायः सभी कुछ औपचारिक-सा हो गया है।

राज्यों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति :

उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, और राजस्थान के साथ-साथ पंजाब सरीखे विकसित राज्य के वित्तीय संकट में फंसने के आसार यही बताते हैं कि राज्य सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था के संचालन में आर्थिक नियमों की उपेक्षा कर रही हैं। राजस्व में कमी और खर्च में लगातार वृद्धि के कारण देश के अनेक राज्यों का वित्तीय संतुलन गड़बड़ाना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। राज्यों पर बकाया कर्ज की स्थिति का आंकलन करने के लिए बनाई गई रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ समिति ने अपनी जो रपट पेश की है, वह चिंतित करने वाली है। इस रपट में कुल मिलाकर राज्यों की ऋणग्रस्तता की भयावह तस्वीर ही उभर रही है। यद्यपि वित्त मंत्रालय इस रपट से चिंतित नजर आ रहा है, लेकिन इसमें संदेह है कि वह राज्य सरकारों को आर्थिक नियमों अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकेगा। जो भी हो, चूंकि राज्य सरकारें आसन्न वित्तीय संकट को लेकर गंभीर नहीं हैं अतः केन्द्र सरकार को कोई न कोई कदम उठाने ही होंगे। यह इसलिए और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि कई राज्यों का वित्तीय ढांचा चरमराने की स्थिति में पहुंच गया है। हालत यह है कि बैंक एवं वित्तीय संस्थान कर्ज के बोझ से दबे राज्यों को ऋण देने से इंकार कर सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनी तो राज्यों को कर्ज से उबारने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के कंधों पर आ पड़ेगी। केन्द्र के लिए इस जिम्मेदारी को वहन करना एक टेढ़ी खीर साबित होगी, क्योंकि स्वयं उसकी वित्तीय स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। यह चिंताजनक है कि जो अनेक राज्य करीब-करीब ऋण जाल में फंस चुके हैं, वे अपनी ऐसी स्थिति के प्रति गंभीर नजर नहीं आते हैं। यह तब है जब इन राज्यों का ऋण उनके सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है। यह तो खतरे की घंटी है, लेकिन इससे अधिक खतरनाक यह है कि खतरे की इस घंटी को सुनने से इनकार किया जा रहा है। यह विडंबना ही है ऐसा करने वालों में अपेक्षाकृत समृद्ध माना जाने वाला राज्य पंजाब भी है। राज्यों की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति का मूल कारण उनकी नारेबाजी प्रधान आर्थिक नीतियां ही हैं। ज्यादातर राज्य सरकारें आम आदमी को लुभाने अर्थात् चुनावी लाभ के लिए वोट बैंक को मजबूत करने के लोभ से ऐसी योजनाओं पर खुलकर पैसा खर्च करती हैं जो आमतौर पर अनुत्पादक ही सिद्ध होती हैं। एक अन्य समस्या यह भी है कि राज्य सरकारें आर्थिक नीतियों का निर्माण तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर करती हैं। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जो अपनी नीतियों का निर्माण दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर गंभीरता से करता हो। हमारे देश में राज्यों के स्तर पर आर्थिक नीतियों में निरंतरता का अभाव एक स्थाई समस्या का रूप ले चुका है। सत्ता परिवर्तन होते ही पिछली सरकार की आर्थिक नीतियों को हाशिए पर डाल देना राज्य सरकारों की प्रवृत्ति बन गई है। एक अन्य घातक प्रवृत्ति राजस्व की अनदेखी कर मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देना भी है। यदि राज्य सरकारों ने वित्तीय अनुशासनहीनता का प्रदर्शन जारी रखा तो वे ऐसे संकट से घिर सकती हैं कि उससे उबरना मुश्किल हो जायेगा। अतः देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने से पहले राजनेताओं को अपने चरित्र को साफ करना होगा और अपनों के बीच अपनी स्वच्छ चरित्र

का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। राजनीति से अपराधिक तत्वों को हटाये बिना देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता है।

राजनीतिज्ञों द्वारा आर्थिक घोटाला

राजनीतिज्ञों द्वारा आर्थिक घोटालों की गूंज भी देश में गाहे-बगाहे होती ही रही। बड़े बड़े आर्थिक अपराधियों की रखा करने का आरोप गुजरे दिनों में देश के शीर्ष राजनीतिज्ञों पर लगता रहा। इस सिलसिले में कई शीर्ष राजनीतिज्ञ भारी छिछलेदार की स्थिति में भी पड़ गए। लगभग 55 अरब रुपये के प्रतिभूति घोटाले से जुड़े कुख्यात आर्थिक अपराधी बंबई के शेयर दलाल हर्षद मेहता ने 16 जून 1993 को सीधे प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव पर आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री राव को उसने एक करोड़ की राशि उस समय दी थी जब राव प्रधानमंत्री बनने के बाद नंदयाल का संसदीय उपचुनाव लड़ रहे थे। हर्षद का आरोप था कि 4 नवंबर 1991 को उसने प्रधानमंत्री को 67 लाख तथा 5 नवंबर 1991 को 33 लाख रुपये दिल्ली स्थिति प्रधानमंत्री निवास-7, रेसकोर्स रोड पर जाकर दिया था। जाहिर है हर्षद मेहता के इस बयान से पूरे देश में सनसनी मच गई थी। 16 जून 1993 को हर्षद मेहता ने बंबई में कहा कि मैंने यह राशि प्रधानमंत्री से राजनीतिक संरक्षण और आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री को दी थी। मेहता ने आरोप के बाद विवाद गहराने पर कहा कि— “प्रधानमंत्री राव को राजनीतिक चंदा देने की बात को सार्वजनिक करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मुझे जान पर खतरा महसूस हुआ तो मुझे विवश हो हलफनामा देना पड़ा। क्योंकि मुझे लगा कि मेरे साथ वही होनेवाला है जैसा नागरवाला या धरम तेजा के साथ कभी हुआ था। उन लोगों की तरह न तो मैं मरना चाहता हूँ न ही यह चाहता हूँ कि मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए।” उल्लेखनीय है कि श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल के शुरुआती दिनों में घोटाला का आरोप नागरवाला पर था। बैंक से भारी रकम श्रीमती गांधी के नाम पर नागरवाल ने ले लिया था। बाद में रहस्यमय परिस्थिति में नागरवाला की हत्या हो गयी थी।

भारतीय राजनीति में यह पहला मौका था जब परोक्ष रूप से भी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री पर सीधे इस तरह का किसी ने आरोप लगाया था। हर्षद मेहता के इस आरोप में चाहे जो भी दम रहा हो लेकिन जाहिर था, खुद प्रधानमंत्री राव भी सकते में आ गए थे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस के अंदरूनी कलह का परिणाम बता रहे थे। राव मंत्रिमंडल के कांग्रेसी दिग्गज अर्जुन सिंह और राव के केंद्रीय मंत्रिमंडल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर भेजे गए शरद पवार के बारे में राजनीतिक गलियारों में अटकलें गर्म थीं कि हर्षद मेहता के ऐसे आरोप के भी यही दोनों नेता सूत्रधार हैं। बहरहाल, कांग्रेस में यह प्रवृत्ति नयी नहीं थी। हमेशा से कांग्रेसी ही कांग्रेसी के दुश्मन रहे हैं। श्रीमती गांधी के जमाने में जबकि किसी की चलती बनती नहीं थी फिर भी कुछ कांग्रेसी नेता उस जमाने में भी चालबाजी करने से बाज नहीं आते थे। प्रधानमंत्री पर हर्षद मेहता के आरोपों को लेकर कई महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी भाजपा की भूमिका भी सूँघ रहे थे। बहरहाल, जो भी हो पर यह बात हर्षद प्रकरण से तो स्पष्ट थी ही कि देश के बड़े-बड़े आर्थिक अपराधी भी कैसे देश के राजनीतिक शतरंज पर महत्वपूर्ण मोहरे बनते रहे हैं। वैसे बड़े-बड़े व्यवसायियों से राजनीतिक गतिविधियों के लिये भारत ही क्या विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में राजनीतिक दल वाले मोटी राशियां लेते रहे हैं। कांग्रेस में केके शाह, एसके पाटिल, रजनी पटेल, ललितनारायण मिश्र और सीताराम केसरी जैसे दिग्गज बड़े व्यवसायियों से पार्टी खाते के लिए धन वसूली का काम करते रहे थे। यह बहुत खुली बात थी। इस तरह राजनीतिक दलों ने आर्थिक अपराधियों का सदैव भरपूर पृष्ठपोषण किया क्योंकि उनके व्यावसायिक गोरखधंधों का हिस्सा बाकायदे राजनीतिज्ञों को मिलता रहा। जून 1993 में जब भारतीय प्रधानमंत्री राव, हर्षद मेहता के आरोपों का सामना कर रहे थे ठीक उन्हीं दिनों में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जॉन मेजर भी ऐसे ही एक आरोप से उलझे थे। दरअसल, ‘संडे टाइम्स’ ने एक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित कर प्रधानमंत्री जॉन मेजर की सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी पर आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी ने एक कुख्यात फरार व्यवसायी आसिल नादिर से 4 लाख 40 हजार पौंड चंदे के रूप में लिया। भ्रष्टाचार के ही आरोप में बंगलादेश के पूर्व राष्ट्रपति एचएम इरशाद को सात

वर्षों के लिए सश्रम कारावास की सजा दी गयी। जापान के प्रधानमंत्री मियाजावा को भ्रष्टाचार के आरोप में गद्दी छोड़नी पड़ी थी। ब्राजील के राष्ट्रपति कोलर को भी भ्रष्टाचार के आरोप में ही पद से जाना पड़ा था। पर इसके बावजूद भ्रष्टाचार को तमाम जनाक्रोश के बाद भी जारी रखने के लिये अपराधी तत्वों का सहारा लेना राजनीतिज्ञों ने कभी नहीं छोड़ा। इसी तरह भ्रष्टाचार और उसकी रक्षा के लिए अपराध, सत्ता का स्थायी चरित्र बन गया।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर देखें तो भारत में लोकतांत्रिक-संवैधानिक मूल्यों के निरंतर झस से भारतीय राजनीति अपराधग्रस्त होती चली गयी। सत्तालोलुपता, सत्ता की मदांधता, सत्ता बचाने के लिए जातीयता, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता के राजनीतिज्ञों के धिनौनें नुस्खें ने समाज को भी अस्थिर कर दिया। इस तरह सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता ने अंततः अपराधी तत्वों की समाज से लेकर सत्ता तक में हैसियत बढ़ा दी। इस संदर्भ में प्रमुख चिंतक नेता रघुकुल तिलक की एक टिप्पणी उल्लेखनीय है—भारत की जनता अपने स्वाभाव और मनोवृत्ति के कारण लोकतंत्र को सफल बनाने की क्षमता नहीं रखती। यहां की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं लोगों को भाग्यवादी और सहनशील होना सिखाती हैं, और इसलिये वे निरंकुश शासन के अत्याचार को सहज ही सहन कर लेते हैं, और सत्ताधारियों का विरोध या आलोचना करना पसंद नहीं करते। इसके अतिरिक्त यहां का समाज जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर इतने छोटे-छोटे टुकड़े में बंटा हुआ है कि कोई भी निरंकुश तंत्र इस फूट से लाभ उठाकर सहज ही अपना आधिपत्य जमा सकता है।”

आज यह सवाल सबकों परेशान कर रहा है कि समाज और राजनीति से अपराधी तत्वों को बाहर कैसे किया जाए पर समर्थ राजनीतिक चिंतकों का मानना है कि यह पहल जबतक आम जनता की तरफ से नहीं होगी तबतक राजनीति से अपराधी तत्वों का उन्मूलन असंभव है। जनशक्ति अंततः निर्णायक है। संवैधानिक मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से बहाली एक समर्थ जनशक्ति ही कर सकती है। समाज ओर समाज के आमजन अगर दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ तय कर लें कि उन्हें हिस्ट्रीशीटर राजनीतिज्ञ नहीं चाहिए तो हिस्ट्रीशीटर और अपराधी सरगना स्वाभाविक रूप से जेल से लेकर अदालत के कठघरे के बीच ही सीमित रहेंगे, संसद और विधानसभाओं को सुशोभित नहीं करेंगे। मुख्य मुद्दा अंततः यह है कि राजनीति और सत्ता मूलक समाज चाहिए या समाज मूलक राजनीतिक और सत्ता चाहिए। आज राजनीति के अपराधीकरण के इस चरम दौर में देश के जन-जन को यह तय करना ही होगा।

संदर्भ स्रोत :

1. कोनोलो, ई० विलियम : पॉलिटिक्स एंड ऐम्बीगुइटी, दि युनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन प्रेस, 1967 पृ०-65-68
2. तथैव
3. कार्डोजो, बी० : दि नेयर ऑफ ज्येडीशियल प्रासेस, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, हेवेन, 1921, पृ०-46-50
4. तथैव
5. कॉक्स, आर्चीबाल्ड : दि रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अमेरिका गवर्नमेंट क्लेरेन्डॉन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1976 पृ०-48-52
6. दास, बी. सी. : इंडियन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1976 पृ०-36-38
7. दास, बी. सी. : पॉलिटिक्स डेवलपमेन्ट इन इंडिया य आशीष पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1978 पृ०-72-75
8. दास, डॉ० एच० एन० : पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, अनमोल पब्लिकेशन (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली, 1998 पृ०-80-85
9. तथैव